



## UGC वनियिम प्रारूप 2025

### प्रलिस के लयल:

[राषट्रीय शकलषा नीतल, समवरती सूची, वशलववलदलयालय अनुदान आयोग](#)

### मेन्स के लयल:

उच्च शकलषा नीतलयीं, शकलषा प्रशासन, शकलषा में समानता

[स्रोत: बज़नेस स्टैंडर्ड](#)

### चर्चा में क्यीं?

भारत के छह राज्यों ने संघीय सवायततता और शैकषकल मानकों पर चतलओं का हवाला देते हुए [वशलववलदलयालय अनुदान आयोग](#) (वशलववलदलयालयों और महावलदलयालयों में शकलषकों तथा अकादमकल स्टाफ की नयुकुतल एवं पदोन्नतल हेतु न्यूनतम योग्यता व उच्च शकलषा के मानकों के अनुरकषण के उपाय) वनियिम प्रारूप 2025 को वापस लेने की मांग की ।

### UGC वनियिम 2025 के प्रारूप में कौन-से प्रमुख प्रावधान कयल गए हैं?

- प्रारूप में [कुलपतलयीं \(VC\)](#) की नयुकुतल में राज्य सरकारों की भूमकल को समाप्त कर इनकी चयन प्रकुरयल को केंद्रीकृत कयल गया है ।
- अनुपालन में वकल रहने वाले वशलववलदलयालयों को UGC योजनाओं से वंचतल कयल जा सकता है तथा वतलत पोषण से वंचतल कयल जा सकता है ।
- प्रारूप में कुलपतल की पदावधकल तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने का प्रस्ताव कयल गया है ।
  - इसके अंतर्गत लोक प्रशासन और लोक नीतल में न्यूनतम 10 वर्ष के वरषलत स्तर के अनुभव वाले गैर-शैकषणकल वयकतलयीं की नयुकुतल की अनुमतल दी गई है ।
- मसौदे में [सनातक पाठयकुरमों के लयल प्रवेश परीकषा अनवलरय](#) करने का प्रस्ताव है ।
- यह मसौदा अकादमकल-उदयुग सहयुग को मज़बूत करता है, अकादमकल प्रकाशन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है, पारदर्शतल बढ़ाता है और शकलषण भूमकलयीं में खललाइयल को शामिल करता है ।
- यह मसौदा अकादमकल-उदयुग की पारदर्शतल, शैकषणकल प्रकाशनों में भारतीय भाषाओं के प्रयुग को प्रोत्साहतल तथा उदयुग-अकादमकल सहयुग को सुदृढ़ करता है, तथा शकलषण पदों पर एथलीटों को शामिल करता है ।

### UGC के बारे में मुख्य बढु कयल हैं?

- उत्पत्तल: राषट्रीय शकलषा प्रणाली स्थापतल करने का भारत का पहला प्रयास 1944 की सार्जेंट रपुर्ट के साथ शुरू हुआ, जसलमें वशलववलदलयालय अनुदान समतल बनाने की सफलरशल की गई थी ।
  - वर्ष 1945 में गठतल इस समतल ने शुरुआत में अलीगढ़, बनारस और दललली वशलववलदलयालयों को वनयलमतल कयल । वर्ष 1947 तक इसका दायरा सभी मौजूदा वशलववलदलयालयों तक वसलतुत हो गया ।
  - वर्ष 1948 में, डॉ. एस. राधाकृषणन के नेतृत्व में वशलववलदलयालय शकलषा आयोग ने बरलटन के मॉडल के आधार पर इसके पुनर्रगठन की सफलरशल की ।
  - वर्ष 1952 में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वशलववलदलयालयों और उच्च शकलषा संस्थानों के लयल अनुदान की देखरेख के लयल वशलववलदलयालय अनुदान आयोग (UGC) को नामतल कयल ।

- वर्ष 1953 में **मौलाना अबुल कलाम आज़ाद** द्वारा औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया, यह वर्ष 1956 में एक वैधानिक निकाय बन गया। UGC का मुख्यालय **नई दिल्ली** में स्थित है।
- **संरचना:** UGC में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार UGC के सभी सदस्यों की नियुक्ति करती है।
- **प्रमुख कार्य:** विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन, रखरखाव, विकास तथा अन्य उद्देश्यों के लिये अनुदान आवंटित और वितरित करना।
  - उच्च शिक्षा में सुधार की सफ़ाई करता है तथा कार्यान्वयन में सहायता करता है।

## भारत में शिक्षा का वनियमन

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया जिससे स्थानीय शिक्षा प्रशासन में राज्य की स्वायत्तता को संरक्षित करते हुए केंद्र सरकार को नीति निर्माण में अधिक भागीदारी की अनुमति मिली।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020** जैसी नीतियाँ और **UGC एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)** जैसी संस्थाओं की भूमिका, समवर्ती सूची से प्रेरित है।
- 7वीं अनुसूची में शिक्षा:

संघ सूची (सूची I)	राज्य सूची (सूची II)	समवर्ती सूची (सूची III)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• इसके तहत संविधान के प्रारंभ में ज्ञात संस्थानों में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय शामिल हैं।</li> <li>• राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (IITs, IIMs, AIIMS, आदि)</li> <li>• केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थान।</li> <li>• उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों (जैसे, UGC, AICTE) में मानकों का समन्वय और निर्धारण।</li> <li>• व्यावसायिक, तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा में शामिल संघ एजेंसियाँ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• राज्य के तहत विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और पुस्तकालयों का निगमन तथा वनियमन (राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों को छोड़कर)।</li> </ul>	शिक्षा, जिसमें तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा, विश्वविद्यालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल हैं (इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं)।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से प्रावधान भारत की शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
2. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय
3. पाँचवीं अनुसूची
4. छठी अनुसूची
5. सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3, 4 और 5

(c) केवल 1, 2 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5 उत्तर: (d)

**??????**

प्रश्न 1. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? वस्तुतः उत्तर दीजिये। (2020)